

दैनिक अखबार जनता के गोठ में खबर प्रकाशित होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, मेहनत की कमाई के लिए भटक रहे ग्रामीण

आमादुला बीट में एक साल से मजदूरी भुगतान लंबित, वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

भुजबल बघेल बकावंड जनता के गोठ। विकासखंड बकावंड के अंतर्गत तोंगकोगेरा क्षेत्र के आमादुला गांव के ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्र भानपुरी के आमादुला बीट में सीपीटी नाली खुदाई का कार्य किया था। ग्रामीणों का कहना है कि काम पूरा हुए लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले दैनिक अखबार जनता के गोठ में भी खबर प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों को भुगतान नहीं मिल सका है।

ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए उन्हें लगातार इंतजार करना



पड़ रहा है। ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्र अधिकारी हेमंत मौर्य और संबंधित बीट गार्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजदूरी भुगतान की समस्या पर अब तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर एक वर्ष बीत जाने के बाद

भी उनकी मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया। उन्होंने भुगतान में देरी के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने मजदूरी की राशि के गबन की आशंका भी जताई है। हालांकि, इस आरोप की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।



ग्रामीणों ने की कड़ी कार्रवाई और जल्द भुगतान की मांग- आमादुला गांव के ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने अपनी लंबित मजदूरी का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है।

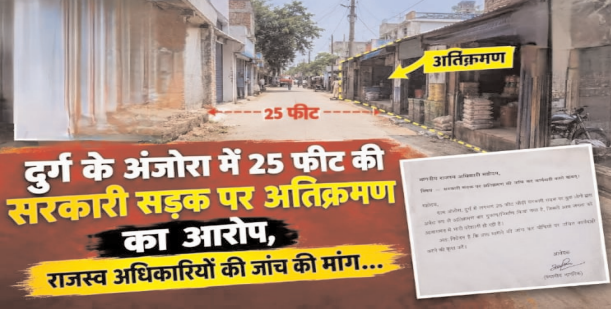
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने मेहनत से अपना काम पूरा क्या है इसलिए उन्हें अपनी ही मजदूरी पाने के लिए बार-बार भटकना नहीं पड़ना चाहिए। अब देखना यह है कि वन विभाग के उच्च उच्चाधिकारी इस मामले में कब संज्ञान लेते हैं और ग्रामीणों को उनकी मेहनत की बकाया राशि कब तक भुगतान होगा।

दुर्ग के अंजोरा में 25 फीट की सरकारी सड़क पर अतिक्रमण का आरोप , राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग

अंचल वर्मा - दुर्ग, उत्तरी जनता के गोठ। दुर्ग - दुर्ग जिले के ग्राम अंजोरा (ढ) में करीब 25 फीट चौड़ी शासकीय सड़क पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। गांव के निवासी भूखनलाल देशमुख ने पुनीत साहू, लेखराम साहू और नारद पर सड़क के हिस्से में बाड़ड़ीवाँल, सेप्टिक टैंक, शौचालय, मकान और दुकान बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने जनदर्शन अधिकारी से मामले की जांच कराने, कथित अतिक्रमण हटवाने और संबंधित राजस्व अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करने की मांग की है।

भूखनलाल देशमुख के मुताबिक, सड़क पर कथित अतिक्रमण के कारण गांव के

किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण लाने-ले जाने में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि इस संबंध में पहले भी राजस्व अधिकारियों और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत नायब तहसीलदार खलसिंह बिसेन से की थी। उनके अनुसार, नायब तहसीलदार ने संबंधित व्यक्तियों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि, देशमुख का दावा है कि आदेश के बावजूद कथित अतिक्रमण नहीं हटया गया। राजस्व विभाग अधिकारी को पत्र लिखा गया। देशमुख ने यह भी बताया कि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के



समक्ष शिकायत रखी थी। उनका आरोप है कि शिकायत के बाद भी न तो सड़क से अतिक्रमण हटया गया और न ही संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

मामले में आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक नागपुरा रत्ना शर्मा को अतिक्रमण

स्थल का निरीक्षण और सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। देशमुख के अनुसार, राजस्व निरीक्षक स्वयं मौके पर नहीं गई और उनके स्थान पर पटवारी गीतानंद पांडे तथा जयप्रकाश यादव को भेजा गया। शिकायतकर्ता ने दोनों पटवारियों की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन को फर्जी बताते हुए उस पर

आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने शासकीय नक्शे की प्रतिलिपि दिखाकर विधिवत सीमांकन करने का आग्रह किया था, लेकिन उनके मुताबिक पटवारियों ने ऐसा नहीं किया। इन आरोपों और प्रतिवेदन से संबंधित तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं होती है। भूखनलाल देशमुख ने जनदर्शन अधिकारी से नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और दोनों पटवारियों की भूमिका की विभागीय जांच कराने तथा सड़क कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ग्रामवासियों को राहत देने के लिए करीब 25 फीट चौड़ी शासकीय सड़क से कथित अतिक्रमण शीघ्र हटवाने का आग्रह किया है।

कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने का कार्य प्रारंभ जिससे क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार , और बड़ेगा व्यापार

अंचल वर्मा - दुर्ग, उत्तरी जनता के गोठ। दुर्ग - जिले के महत्वपूर्ण कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया मार्ग (राज्य मार्ग क्रमांक-21) के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग के विकास के लिए डामरीकरण सहित आवश्यक संरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने के साथ आवागमन और व्यापार अधिक सुगम और सुरक्षित होने की उम्मीद है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के तहत कुल 26.60 किलोमीटर लंबे मार्ग का उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए लगभग 24 करोड़ 6 लाख 23 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। परियोजना की प्रशासकीय



स्वीकृति 24 नवंबर 2025 को जारी हुई थी, जबकि कार्यादेश 8 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है।

60 मिलीमीटर डामरीकरण , सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की

योजना - परियोजना के अंतर्गत सड़क पर 60 मिलीमीटर डीबीएम तथा 40 मिलीमीटर बीसी से डामरीकरण 3 निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दो चौड़े साइड शोल्डर प्रस्तावित हैं। पुलिस सहित आवश्यक संरचनात्मक कार्य भी किए जाएंगे। इन कार्यों से सड़क

की मजबूती बढ़ने के साथ जल निकासी और यातायात व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है।

किसानों , व्यापारियों और विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ - कुम्हारी- अहिवारा - पथरिया मार्ग भौगोलिक संपर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मार्ग छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को जोड़ने के साथ क्षेत्र के प्रमुख मार्गों एवं आवागमन केन्द्रों तक पहुंच उपलब्ध कराने में सहायक है। इसके अलावा, कन्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह मार्ग महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है।

सड़क के उन्नयन से किसानों को कृषि उपज मंडियों तक उपज पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। वहीं, व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और दैनिक यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने की उम्मीद है। सड़क की स्थिति सुधरने से यात्रा समय और परिवहन लागत

में भी कमी आ सकती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा मिलेगा जिसके साथ ही बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। कृषि उत्पादों और अन्य आवश्यक सामग्रियों के परिवहन में सुविधा होने से स्थानीय बाजारों को लाभ मिल सकता है। साथ ही, क्षेत्र के गांवों का संपर्क मजबूत होने से शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। कुल मिलाकर, कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया मार्ग का सुदृढ़ीकरण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है। निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा होने पर क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

बलरामपुर में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद? सरपंच संघ अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी का आरोप, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

बलरामपुर (जनता के गोठ) : बलरामपुर जिले के वाड़फनगर क्षेत्र में कथित रेत माफियाओं की दबंगई और पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जनपद पंचायत वाड़फनगर के सरपंच संघ अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत प्रेमनगर के सरपंच राजनारायण सिंह प्रस्ते के साथ जातिसूचक गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है। मामले में बसंतपुर थाने में शिकायत किए जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए सरपंच संघ एवं आदिवासी समाज ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।



जनप्रतिनिधि की सुरक्षा पर सवाल, जातिगत अपमान का आरोप- ज्ञापन के मुताबिक, सरपंच संघ अध्यक्ष राजनारायण सिंह प्रस्ते के साथ कथित तौर पर जातिगत टिप्पणी करते हुए अभद्रता और गाली-गलौज की गई। आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे केवल एक व्यक्ति के सम्मान का मामला नहीं, बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सुरक्षा और सामाजिक सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप- मामले की लिखित शिकायत बसंतपुर थाने में दिए जाने की बात ज्ञापन में कही गई है। इसके बावजूद कार्रवाई में देरी को लेकर सरपंच संघ ने नाराजगी जताई है। प्रतिनिधियों ने आशंका व्यक्त की है कि यदि ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ सकते हैं। वहीं, कथित रेत माफियाओं को स्थानीय स्तर पर संरक्षण मिलने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

एसडीओपी को ज्ञापन, सात दिन में कार्रवाई की मांग- सरपंच संघ एवं आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी), वाड़फनगर को ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत तथ्यों के अनुरूप उचित कानूनी कार्रवाई करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है।

प्रतिनिधियों ने प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

थाना घेराव और चक्काजाम की चेतावनी- मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में बसंतपुर थाना घेराव, चक्काजाम और व्यापक धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इस

चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन के सामने मामले का निष्पक्ष निराकरण करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

अब पुलिस के रुख पर टिकी निगाहें- मामले ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं-क्या शिकायत पर समयबद्ध जांच होगी? क्या कथित धमकी और जातिगत अपमान के आरोपों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी? और क्या सरपंच संघ अध्यक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? इन सवालों का जवाब अब पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई से मिलेगा।

फिलहाल, सरपंच संघ और आदिवासी समाज की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दीधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। वहीं, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी जरूरी है।

पत्नी पर ईंट से जानलेवा हमला करने का आरोपी पति गिरफ्तार

सिर और चेहरे पर किए थे वार, घटनास्थल से ईंट का टुकड़ा बरामद

जनता के गोठ/ओंकार साहू बलोदाबाजार जिला थाना हथबंद क्षेत्र के ग्राम गोरदी में पत्नी पर ईंट से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी के सिर और मुंह पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा भी जब्त किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 22 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 3 बजे की है। सूचना मिलने पर प्रार्थी अन्य ग्रामीणों के साथ आरोपी सुभाष दास मानिकपुरी के घर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी फलता मानिकपुरी कमरे



के अंदर खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। आरोप है कि सुभाष ने जान से मारने की नीयत से पत्नी के सिर और मुंह पर ईंट से हमला किया था। घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना हथबंद में अपराध क्रमांक

234/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) और 85 में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुभाष दास मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पृच्छाछ की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। पुलिस ने 23 अक्टूबर

को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में की गई।

गिरफ्तार आरोपी: सुभाष दास मानिकपुरी (33), पिता हेमदास मानिकपुरी, निवासी ग्राम गोरदी, थाना हथबंद, जिला बलोदाबाजार-भाटापारा।

शिक्षक पात्रता परीक्षा को ऑफलाइन कराने की मांग, शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने जताया आभार, ओएमआर शीट से परीक्षा आयोजित करने की उठाई मांग

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ जगदलपुर। सेवारत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़े शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मुद्दे पर सकारात्मक पहल के लिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। बस्तर प्रवास के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर विभागीय टीईटी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित पद्धति के बजाय ओएमआर शीट के माध्यम से ऑफलाइन आयोजित कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ एवं अदरूनी क्षेत्रों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने पर शिक्षकों को नेटवर्क, सर्वर और बिजली जैसी तकनीकी समस्याओं का



सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में परीक्षार्थियों को अनावश्यक परेशानी होने की आशंका है। एसोसिएशन ने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए ओएमआर आधारित ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना अधिक सुविधाजनक होगा। विशेषकर लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों की परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यक्ष पद्धति से परीक्षा

आयोजित करने का निर्णय समय की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता एवं सहानुभूतिपूर्वक सुना। उन्होंने शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक एवं उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, प्रांतीय संगठन

मंत्री राजेश गुप्ता, बस्तर जिलाध्यक्ष डॉ. लुदरसन कश्यप, जिला सचिव मो. ताहिर शेख, कोषाध्यक्ष अमित पाल, जिला सह सचिव जगदीश पात्र, प्रवक्ता डॉ. तुलादास मानिकपुरी, जिला प्रचार सचिव गजराज सिंह, जिला प्रचार मंत्री रामप्रसाद ठाकुर, जिला संगठन मंत्री ओमप्रकाश पटेल तथा विकासखंड अध्यक्ष जगदलपुर मनीष ठाकुर सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जुनावनी के जंगल में चटाई कार्य करने वाले 70 ग्रामीणों को एक साल से नहीं मिली मजदूरी

वन विभाग के अधिकारियों पर भुगतान के नाम पर टालमटोल का आरोप, मेहनत की कमाई के लिए भटक रहे महिला-पुरुष मजदूर

भुजबल बघेल बकावंड जनता के गोठ। बकावंड विकासखंड के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बकावंड के जुनावनी स्थित बड़े जंगल में चटाई का कार्य करने वाले लगभग 70 महिला-पुरुष मजदूरों को एक वर्ष बीत जाने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के संबंधित बीटागार्ड और रेंजर से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी मेहनत की कमाई अब तक नहीं मिली है। इससे मजदूरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने एक वर्ष पहले जंगल में चटाई बनाने का कार्य पूरी मेहनत और लगन से किया था। काम पूरा होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मजदूरी



का भुगतान समय पर कर दिया जाएगा, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी उन्हें अपनी मजदूरी नहीं मिली है। अब अपनी मेहनत की राशि पाने के लिए ग्रामीण वन विभाग के अधिकारियों के चक्र काटने को मजबूर हैं।

आज देंगे, कल देंगे कहकर टालमटोल का आरोप- ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी वे मजदूरी भुगतान के लिए परेशान ग्रामीणों में विमल, चमरोने, सोनादेई, सोमारी, डरमीला, बुधली, बालमती,

का आश्वासन दिया जाता है। लंबे समय से केवल आश्वासन मिलने के बावजूद भुगतान नहीं होने से मजदूरों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरी के लिए बार-बार अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

70 मजदूरों की मजदूरी भुगतान की मांग- मजदूरी भुगतान के लिए परेशान ग्रामीणों में विमल, चमरोने, सोनादेई, सोमारी, डरमीला, बुधली, बालमती,

सोनमती, सुकरी, पंचमी, लबूधर, रोमा, तुला, सुमनी, शांति, सुशीला, जानकी, रैती, कमलावती, बागवती, मनाय, कुमारी, लकमी, बुदर, करण, गुड्डू, जयराम, मोती, और तीरलचन सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग के संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि मामले की जांच कर चटाई कार्य में लगे सभी मजदूरों की बकाया मजदूरी का जल्द भुगतान कराया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों से रात मिल सके।

संपादकीय

ट्रंप पर कितना भरोसा करें

यह समझना कठिन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कथन पर कितना भरोसा किया जाए कि वे भारत से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के निकट हैं? वे और उनके सहयोगी इसके पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि हम भारत से व्यापार समझौता करने के करीब हैं, लेकिन महीनों बीत गए और ऐसा होने की नीबत नहीं आई। ट्रंप के दावों पर यकीन करना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि वे अपनी ही बातों से मुकरने के आदी हो चुके हैं। अभी हाल में तो वे उस कानून पर अमल टालने को भी बाध्य हुए, जिसके तहत भारत, चीन समेत उन पांच देशों पर सी प्रतिशत टैरिफ लगाने जा रहे थे, जो रूस से तेल आयात करते हैं। उन्हें अपने कदम इसलिए पीछे खींचने पड़े, क्योंकि अमेरिका खुद रूस से डीजल खरीदने को बाध्य हो गया। इसके चलते तेल एवं गैस के बढ़ते मूल्यों की तपिश अमेरिका को भी झेलनी पड़ रही है-और वह भी ऐसे समय, जब वहां मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप की साख दांव पर है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि अमेरिका को अंततः यह आभास हुआ कि ऊर्जा संकट के समाधान में भारत का सहयोग लेना आवश्यक है। इसका एक प्रमाण उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जामनगर की रिलायंस रिफाइनरी का दौरा करना है। वहां जाने से पहले उन्होंने भारत को कच्चे तेल की रिफाइनिंग के मामले में महाशक्ति कहा। तथ्य यह भी है कि अमेरिका इस कोशिश में है कि भारत वेनेजुएला से अधिक से अधिक कच्चा तेल खरीदे और उसे शोधित कर निर्यात करे, ताकि ऊर्जा संकट से जूझ रहे अन्य देशों के साथ उसे भी राहत मिले। भारत वेनेजुएला से जितना अधिक कच्चा तेल खरीदेगा, अमेरिका को उतना ही अधिक लाभ होगा, क्योंकि उसने वहां के तेल स्रोतों को एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वेनेजुएला के कच्चे तेल की गुणवत्ता ऐसी है कि सबके लिए उसका शोधन करना आसान नहीं।

आज का राशिफल

मे़ष राशि : खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए दिखावे पर पैसा खर्च करने से बचें। अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत की तारीफ होगी और अधिकारी भी आपके प्रदर्शन से खुश नजर आएंगे।

वृष राशि : आज आपकी कार्यकुशलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। भाग्य का साथ मिलने से जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता की उम्मीद रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा बड़ा फैसला भी संभव है।

मिथुन राशि : आज अपनी बुद्धि और समझदारी का सही इस्तेमाल करने का दिन है। आपके कुछ फैसले आसपास के लोगों को चौंका सकते हैं, लेकिन उनका असर सकारात्मक रह सकता है।

कर्क राशि : आज आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं, हालांकि मन में हल्का तनाव भी बना रह सकता है। परिवार में किसी मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है।

सिंह राशि : आज आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं, लेकिन अचानक आने वाले खर्च आपकी योजना को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

कन्या राशि : आज अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। आपकी कही हुई एक छोटी सी बात भी सामने वाले पर बड़ा असर डाल सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

तुला राशि : आज कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। कारोबार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। वृश्चिक राशि : आज अपनी बातों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। गलत समझ पर कहा गया एक शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। अनजान व्यक्ति की बातों में आकर फैसला न लें।

धनु राशि : आज अचानक कोई लाभ मिल सकता है और ऐसी चीज हाथ लग सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

मकर राशि : आज मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेगी। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और साथी के साथ खुबसूरत पल बिताने का मौका मिलेगा। संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। कुंभ राशि : आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल नजर आ रहा है। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिलने की अच्छी संभावना है। किसी रिश्तेदार के घर शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।। दें। मीन राशि : आज परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। आपके दिमाग में कई नए विचार आएंगे और अगर उन्हें सही समय पर अमल में लाया, तो अच्छा फायदा मिल सकता है।

तिरंगे की आड़ में अराजक व्यवहार

वर्ष 2004 से पहले आम लोगों को अपने घरों या कार्यालयों पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। वे ऐसा केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही कर सकते थे। हर कोई सभी दिन अपने घरों, कार्यालयों और वाहनों पर तिरंगे का उपयोग कर सके, इसके लिए उद्योगपति नवीन ज़िंदल ने लंबी लड़ाई लड़ी। जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि लोग कभी भी सम्मान और गरिमा के साथ अकेले घर, दुकान, दफ्तर पर तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठन और आम लोग तिरंगे का उपयोग करने लगे। पहली बार अन्ना आंदोलन के समय बड़े पैमाने पर तिरंगे का उपयोग हुआ। धीरे-धीरे कुछ लोग तिरंगे की आड़ लेकर मनमानी और यहां तक कि लोगों को तंग करने का काम भी करने लगे। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में एक सड़क घेरेकर जो लंबा धरना चला, उसमें भी तिरंगा लहराया गया था। जेएनयू में छात्र नेता रहा शरजील इमाम उसी दौरान जब इस कानून के विरोध में आग उगल रहा था और यहां तक कि चिकन नेक यानी सिलिगुड़ी कारिडोर को पूर्वांचल से शेष भारत को अलग करने की जरूरत जता रहा था, तब उसके मंच पर भी तिरंगा लहरा रहा था। कृषि कानूनों के विरोध में करीब 13 महीने तक एक तरह से दिल्ली घेरेकर बैठे संगठनों ने भी तिरंगे का इस्तेमाल किया। तब उनके धरने के कारण हर दिन लाखों लोग परेशान हो रहे थे। इन संगठनों ने गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैक्टर रैली निकाली, वह बिल्कुल ही शांतिपूर्ण नहीं थी। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर धावा बोलकर वहां जमकर उत्पत मचाया, जबकि उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाया जाएगा और देशभक्ति के गीत बजाए जाएंगे। इसके विपरीत तिरंगे की आड़ में अराजकता फैलाई गई। इस घटना में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी पीटे गए। तिरंगे की आड़ में अराजक हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। अब ही जब दिल्ली में जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन वाले स्थलों की सूची से बाहर किया गया तो काकोरोज जत्ता पार्टी के समर्थकों ने कनाट प्लेस पर तिरंगा फहराने की जिद पकड़ी। लहरा दो तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सीरव दास को जंतर-मंतर पर जबरन तिरंगा फहराने से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के विरोध में किया गया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस कनाट प्लेस में किसी को तिरंगा नहीं फहराने देना चाहती थी। उसने सीजेपी नेता अभिजीत दीपके से कहा था कि वे 11 लोगों के साथ वहां तिरंगा फहरा सकते हैं, जब तक उसी को इरादा तिरंगे के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने का था। वे अच्छे से जानते थे कि त्योहार के कारण कनाट प्लेस में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ती है और वहां किसी तरह के प्रदर्शन से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन सीजेपी को न तो व्यापारियों के नुकसान की कोई परवाह थी और न ही आम लोगों को होने वाले परेशानी की।

जानलेवा

- **तलित गर्ग**

सर्दियों ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है कि देश के अनेक शहरों की हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का तेजी से बिगड़ना इस बात का संकेत है कि प्रदूषण का संकट अब केवल सर्दियों की मौसमी समस्या नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन, शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में दमघौंढ़ धुंध, आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई और अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या के साथ यह संकट सामने आता है। विर्डंबना यह है कि समस्या के कारणों की पहचान होने और उपायों की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद हम हर वर्ष उसी त्रासदी को दोहराने के लिए विवश दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि क्या स्वच्छ हवा में सांस लेना भी अब नागरिकों के लिए एक दुर्लभ सुविधा बनकर रह जाएगा? वायु प्रदूषण किसी एक कारण या किसी एक राज्य की देन नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक स्वास्थ्य, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी, कचरा और जैविक पदार्थ जलाना, ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन तथा कृषि अवशेषों का दहन इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। सर्दियों में तापमान गिरने, हवा की गति कम होने और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषक जमीन के निकट जमा हो सकते हैं। इससे प्रदूषण का प्रभाव अधिक गंभीर हो जाता है। इस प्रकार मौसम समस्या को बढ़ाता अवश्य है, लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाले

भस्मासुर क्यों बन रहे हैं शिवराज?

- **राकेश अवल**

मप्र की जिस भाजपा सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी ने अपनी मेहनत से बनाया था,उसी को अब दोनों मिलकर अस्थिर करने में क्यों जुटे हैं ?

मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी की मेहनत से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था लेकिन भाजपा हाईकमान ने दोनों को ही मप्र का मुख्यमंत्री न बनाकर उनके सपने पर पानी फेर दिया था.इन दोनों की जगह तीसरी कतार के नेता डाक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था.

पिछले तीन साल से चौहान और सिंधिया की जोड़ी मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव को अपनी कठुवतुली बनाने की कोशिश कर रही थी किंतु उन्हे कामयाबी नही मिली.नतीजा अब दोनों का असंतोष फूट पड़ा है.शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा हाईकमान ने हालांकि मोदी मंत्रिमंडल में जगह दे दी है पर वहां दोनों की न कोई हैसियत है और न पहचान.दुखी होकर ये दोनों मप्र की राजनीति में ही दिलचस्पी ले रहे हैं.लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों को पैर ही नहीं जमाने दे रहे.



मूल कारण मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उनके अपर्याप्त नियमन से जुड़े हैं।

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति इस संकट का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के अनेक शहर एक-दूसरे से जुड़े वायु क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसलिए केवल दिल्ली की सीमाओं के भीतर उपाय करने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हवा किसी प्रशासनिक सीमा को नहीं मानती, वह प्रदूषण को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाती है। अतः समाधान भी क्षेत्रीय सहयोग, साझा जवाबदेही और समन्वित कार्ययोजना पर

भस्मासुर क्यों बन रहे हैं शिवराज?



शिवराज सिंह चौहान ने तो बुदनी के आदिवासियों के उत्पीडन की आड में मोहन सरकार के विरोध में न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि धरना तक दे दिया.चौहान सैकड़ो आदिवासि का मार्च लेकर भोपाल जाने ही वाले थे लेकिन पार्टी हाईकमान ने अपना वोटो लगा दिया.मजबूरी में चौहान को सीजफायर करना पड़ा.लेकिन उनके मन में आग सुलग रही है.बुझी नही है.ये आग दोबारा कब? किस रूप में भडकेगी कोई नहीं जानता.

शिवराज की तरह ही सिंधिया भी कसमसा रहे हैं.सरकार में कोई इन स्वयंभू महाराज की सुन नही रहा.यहाँ तक कि अपने गृहजिला ग्वालियर में तक उनकी पसंद के कलेक्टर और एसपी तक नही हैं.सिंधिया भी अपनी कूट्ट पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दो जुला कलेक्टरों पर भडककर निकाल दिया हैं.शीतला माता मंदिर हादसे के बाद सिंधिया पर एक बार फिर ग्वालियर के

कलेक्टर और एसपी को हटाने का दबाव है लेकिन वे असहाय नजर आ रहे हैं.

इस समय मोहन सरकार को खतरा बाहर से कम भीतर से ज्यादा है.ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी मोहन सरकार के गले की हड्डी बन चुका है.पार्टी के नेता डाक्टर नरोत्तम मिश्रा भी लगातार इसी मुद्दे पर राजनीति शुरू कर चुके हैं.वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय,और प्रहलाद पटेल का असंतोष तो पहले ही अनेक मौकों पर उजागर हो चुका है.

अब देखना ये है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कब तक भस्मासुर की भूमिका में रहते हैं ?उनके पास विधायक भी हैं और सांसद भी.ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभी तक शिवराज सिंह चौहान के खेमे से अलग नही हुए हैं.शिवराज सिंह चौहान की नजर अब 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है.

बड़े संकट की ओर बढ़ता यूरोप



राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं के प्रति अविश्वास में बदल सकता है। इसलिए सरकार को हिंसा कर रहे लोगों और शांतिपूर्ण ढंग से मांगें रखने वालों के बीच स्पष्ट अंतर करना होगा।

बढ़ते सार्वजनिक ऋण और सरकारी उधारी की लागत ने फ्रांस पर बजट घाटे को नियंत्रित करने का दबाव बढ़ा दिया है। संसद में 2027 के बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग 43 अरब यूरो की घाटा-कटौती उपाय प्रस्तावित हैं, लेकिन शिक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं पर खर्च घटाने से जनता का असंतोष और बढ़ सकता है। दूसरी ओर, बिना पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के सरकारी खर्च बढ़ाने से वित्तीय स्थिरता और निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है। बाजारों की प्रतिक्रिया भी इस संकट की गंभीरता को दर्शाती है।

फ्रांस के सरकारी बांड पर दबाव बढ़ा, यूरो कमजोर हुआ और फ्रांसीसी शेयर बाजार का प्रदर्शन यूरोपीय बाजारों की तुलना में खराब रहा। यदि

राजनीतिक अस्थिरता लंबे समय तक बनी रही, तो निवेश प्रभावित हो सकता है। उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर पड़ेगा। व्यवसायों को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेष रूप से छोटे दुकानदारों के लिए हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई कठिन होगी। जिस आर्थिक असुरक्षा ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, वही हिंसा के कारण और गहरी हो सकती है।

आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण भी फ्रांस की स्थिति को गंभीर बना रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है और लगभग छह महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। संसद में तीन प्रमुख राजनीतिक धड़ों के बीच गहरे मतभेदों के कारण सरकार के लिए सहमति बनाना कठिन है। दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन सरकार को कानून-व्यवस्था संबंधी विफलताओं को मुद्दा बना रही हैं, जबकि वामपंथी नेता जॉ-लुक मेलांशों सरकार और पुलिस की भूमिका

गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खुले मैदान में खेलने से रोकना पड़े, बुजुर्ग सुबह की सैर छोड़ने को विवश हों और श्रमिकों को जहरीली हवा में काम करना पड़े, तो यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि जीवन की गरिमा और नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। एयर प्यूरीफायर या मास्क कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत बचाव में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे स्वच्छ हवा की सार्वजनिक व्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकते। प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, वाहनों और उद्योगों पर नियंत्रण तथा अन्य आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इन उपायों की सफलता केवल आदेश जारी करने से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी से सुनिश्चित होती है। यदि प्रतिबंधों का उल्लंघन होता रहे, निर्माण स्थलों पर धूल उड़ती रहे और कारना खुले में जलता रहे, तो सरकारी घोषणाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकतीं। सरकार को प्रदूषण के चरम पर पहुंचने की प्रतीक्षा करने के बजाय सितंबर-अक्टूबर से ही तैयारी शुरू करने देनी चाहिए। प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण, सड़कों की नियमित सफाई, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और वाहनों के उत्सर्जन की जांच पहले से सुनिश्चित कर की जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करना दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।

धरती तप रही है, दुनियाँ के वादे अधूरे हैं !

- **किशन सनमुखदास भावनानी** वैश्विक स्तरपर दुनियाँ आज विकास, आधुनिकता और तकनीकी प्रगति के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है,लेकिन इसी विकास की कीमतहमारा ग्रह बढ़ते तापमान, भीषण गर्मी,अनियमित वर्षा,बाढ़, सूखे और चरम मौसमी घटनाओं के रूप में चुका रहा है वैश्विक मंचों पर जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते किए जा रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन घटाने के संकल्प दोहराए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों की रफतार जलवायु संकटकी गंभीरता के अनुरूप नहीं है मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि इसी चिंताजनक स्थिति के बीच संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूपएनईपी) ने बुधवार दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को अपनी नई इमिश्यंस गैप रिपोर्ट 2026: द पॉइंट ऑफ रिटर्न जारी की है रिपोर्ट का संदेश स्पष्ट है दुनियाँ के सामने अब केवल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की चुनौती नहीं,बल्कि तापमान में होने वाली संभावित वृद्धि को सीमित करने और भविष्य में उसे फिर से सुरुक्षित स्तर तक लाने की कठिन परीक्षा भी है। रिपोर्ट के अनुसार,औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य बिना या बहुत सीमित सीमा तक तापमान बढ़ने की स्थिति में हासिल करना अब संभव नहीं रह गया है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि मानवता के पास कुछ करने का अवसर समाप्त हो गया है।अब सबसे बड़ी जरूरत तापमान में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को न्यूनतम रखने, उसके दुष्प्रभावों को कम करने और इस

सदी के अंत तक तापमान को दोबारा 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे लाने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने की है।

साथियों बात अगर हम 1.5 डिग्री का लक्ष्य क्यों बना दुनियाँ के लिए सबसे बड़ी चिंता ? को समझनेकी करें तो अब पेरिस जलवायु समझौते के तहत दुनियाँ के देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास करने का संकल्प लिया था। लेकिन वर्षों से जारी अपर्याप्त जलवायु कार्रवाई ने परिस्थितियों को बेहद गंभीर बना दिया है। यूपएनईपी की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को बिना या बहुत सीमित ओवरशूट के भीतर बनाए रखने की संभावना अब समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब है कि आने वाले दशकों में तापमान इस सीमा से ऊपर जा सकता है हालांकि वैज्ञानिकआकलन यह भी बताता है कि अगर उत्सर्जन में तेजी से और बड़े पैमाने पर कटौती की जाए, तो तापमान में अधिकतम वृद्धि को सीमित करना और इस सदी के अंत तक फिर से 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर लौटने की लागभग 50 प्रतिशत संभावना वाला रास्ता अभी भी मौजूद है रिपोर्ट के सबसे कम संभावितओवरशूट वाले परिदृश्य में मध्य शताब्दी के आसपास तापमान वृद्धि लगभग 1.7 से 1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की परिकल्पना की गई है। लेकिन इस दिशा में सफलता हासिल करने के लिए दुनिया की कोकल घोषणाएं नहीं,बल्कि अभूतपूर्व गति से वास्तविक उत्सर्जन कटौती करनी होगी।

की आलोचना कर रहे हैं। संकट के समाधान के लिए आवश्यक राजनीतिक सहयोग के स्थान पर आरोप-प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं।

फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव पूरे यूरोप में दिखाई दे रहा है। इटली, बेल्जियम और पुर्तगाल में भी प्रदर्शन तथा झड़पें हुई हैं, जबकि स्पेन में आवास और वेतन के मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन की तैयारी है। अल्बानिया में भी सरकार विरोधी और छात्र आंदोलनों ने हिंसक रूप लिया। इन देशों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन महंगाई, आवास की बढ़ती लागत, कम वेतन और सरकारी नीतियों से असंतोष जैसी समस्याएं समान हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि ने परिवारों के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाला है। कमजोर आर्थिक विकास के कारण लोगों की आय आवश्यक खर्चों के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही है।

आने वाले महीनों में कई यूरोपीय देशों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आर्थिक असंतोष और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मेल अधिक खतरनाक हो सकता है। यदि पारंपरिक दल जनता को ठोस समाधान देने में विफल रहते हैं, तो अतिवादी ताकतों को समर्थन मिल सकता है। जटिल आर्थिक समस्याओं के सरल समाधान देने का दावा करने वाले दल जनता की निराशा का लाभ उठा सकते हैं। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा और गठबंधन तथा सहमति के आधार पर शासन चलाना और कठिन हो सकता है।

कुल मिलाकर, फ्रांस का संकट पूरे यूरोप के लिए एक चेतावनी है। लोकतंत्र की स्थिरता केवल पुलिस और प्रशासन की क्षमता पर निर्भर नहीं करती, इसके लिए नागरिकों का यह विश्वास भी आवश्यक है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है, लेकिन किफायती आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार और विश्वसनीय सार्वजनिक सेवाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।



संक्षिप्त समाचार

राशन दुकान संचालन के लिए आवेदन 4 नवम्बर तक

बिलासपुर। जिले के कोटा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान जोगीपुर, मिट्ठू नवागांव, करबा, पुडु, पोंड़ी (402003032), मोहली, लूफ, उपका, शक्तीबहरा, कुरबार, नगोई, करी, नवागांव (स), लमकेना, तुलुफ पोंड़ी (402003105) के आबंटन के लिए 4 नवम्बर 2026 तक बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वृहदाकार आदिम जाति बहुदेशीय सहकारी समिति (लेम्पस) एवं वन सुरक्षा समितियों के आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को दुकान आबंटन हेतु आवेदन करने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाली सहकारी समिति एवं महिला स्व सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत हो तथा उसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार किया जाएगा। बंद लिफाफे के ऊपर जिस दुकान के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम व आई.डी. अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवम्बर 2026 को दोपहर 3 बजे तक है। नियत तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन करने के लिए समिति एवं संस्थान के पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति, समिति, संस्था, पंचायत के सभी सदस्यों के नाम, पते व आधार की सत्यापित छायाप्रति की जानकारी, आवेदक समिति, समूह, पंचायत का बचत बैंक खाता की प्रमाणित छायाप्रति एवं अंतिम 3 माह का स्टेटमेंट, समिति एवं संस्था का शपथ पत्र आदि होना आवश्यक है।

शासकीय राशन दुकान मचखण्डा के संचालन हेतु आवेदन 30 अक्टूबर तक

बिलासपुर। शासकीय उचित मूल्य की दुकान मचखण्डा के आबंटन के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वृहदाकार आदिम जाति बहुदेशीय सहकारी समिति (लेम्पस) एवं वन सुरक्षा समितियों के आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ संस्था के पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि, बैंक खाते की सत्यापित प्रतिलिपि, विगत 3 माह का बैंक स्टेटमेंट, दुकान संचालन संबंधी संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि, संस्था द्वारा विगत तीन माह में की गई गतिविधियों के संबंध में समूह का कार्यवाही, प्रस्ताव पंजी की सत्यापित प्रतिलिपि एवं संस्था प्रमुख द्वारा आवेदन के संबंध में निष्पादित शपथ पत्र मूलतः संलान करना अनिवार्य है।

आरसीए एवं आरसीए बी के बीच अभ्यास मैच खेला गया

राजनांदगांव। ओपर बैट्समेन रुद्र दशेरिया 20 चौके एवं 3 छके के मदद से 171 बाल में 118 रन बनाया। ट्राफी मैन ऑफ़द मैच दिया गया। ओपनिंग जोड़ी में निहाल और रौनक मैदान में उतरे। रौनक 0 रन बनाकर राजवीर में बोल्ड ऑउट हो गये। पहला विकेट 1 रन पर रौनक के रूप में आऊट हो गया। अर्जुन 20 रन, प्रिस 17 रन, निहाल सोनकर 6 रन पूरी टीम 232 रन बनाकर आल आऊट हो गई। एकस्ट्रा के रूप में 56 रन मिला जिसमें व्हाईट 39, एल बी एक, नो बाल 7 रन प्राप्त हुआ। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीए बी की टीम ओपनिंग जोड़ी में शिवा और चीकू पहला विकेट 4 रन के योग पर ऑफ़स्पिन विजेन्द्र यादव के बाल पर बोल्ड आउट हो गया। क्रमशः राजवीर 20 रन नाटआऊट, 12 रन चीकू, शिवा 4 रन, देविका 8 रन, 21 रन व्हाईट, नो बाल 3, 78 रन पर पूरी टीम आल आऊट हो गई। विजेन्द्र यादव 3 विकेट, निहाल 1, ईशान साहू 3 विकेट प्राप्त हुए।

कोसीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 7.20 लीटर देशी शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, 753,200 की संपत्ति जब्त

सारंगढ़-। जिले में अवैध शराब के कारोबार और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोसीर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 7.20 लीटर देशी शराब और परिवहन में प्रयुक्त हिरो पैंशन प्लस मोटरसाइकिल सहित कुल 53,200 रुपये की संपत्ति जब्त की है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अभियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल में शराब रखकर कोसीर से भाटागांव की ओर बिक्री के लिए जा रहे हैं।

सेवा सेतु केंद्रों से नागरिकों को मिलें सुगम और त्वरित सेवाएं, प्रबंधकों को दिया गया प्रशिक्षण...

■ त्रुटि रहित आवेदन भरने पर जोर, केंद्रों में सेवा शुल्क की सूची प्रदर्शित करने के निर्देश

बिलासपुर। जिले के नागरिकों को सेवासेतु पोर्टल के माध्यम से सरल, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवासेतु केंद्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी बिलासपुर द्वारा खारंग जल संसाधन विभाग परिसर स्थित प्रार्थना सभा कक्ष में सेवासेतु केंद्र प्रबंधकों की समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें नगर निगम क्षेत्र एवं सभी विकासखंडों के

केंद्र प्रबंधकों के साथ राजस्व विभाग के तहसीलदार, रीडर और भू-अभिलेख शाखा के कर्मचारी शामिल हुए। प्रशिक्षण में केंद्रों के माध्यम से किए जा रहे ऑनलाइन आवेदनों तथा अपूर्ण आवेदनों को सुधार के लिए वापस भेजने और निरस्त किए जाने के कारणों की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रबंधकों को विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल पर उपलब्ध नई सेवाओं की जानकारी दी गई। केंद्र प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने से पहले संबंधित सेवा के लिए निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों की सूची से मिलान अवश्य करें। पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत होने से त्रुटियों के कारण आवेदन वापस होने की स्थिति कम



होगी और नागरिकों को सेवाओं का बैठक में सभी कॉमन सर्विस सेंटर एवं लाभ समय पर मिल सकेगा। समीक्षा सेवासेतु केंद्रों पर राज्य कार्यालय से

कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की संभागीय बैठक सम्पन्न

फसल विविधीकरण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर जोर

■ खरीफ 2026 की समीक्षा एवं रबी 2026-27 की कार्ययोजना पर हुई विस्तृत चर्चा

बिलासपुर। राज्य शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं कृषि सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी की अध्यक्षता में शुरुवार को कृषि एवं संबद्ध विभागों की संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित कृषि गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी रबी वर्ष 2026-27 के कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती-किसानी के साथ कुकुटपालन, मछलीपालन, बकरीपालन और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर योजनओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में खरीफ सीजन के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा के साथ रबी सीजन की तैयारियों



पर चर्चा किया गया। कृषि एवं संबद्ध विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने कहा कि खरीफ सीजन में बिलासपुर संभाग में अच्छा कार्य हुआ है, जिसमें सम्भाग के सभी जिलों का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में भी इसी तरह हम सबको सामंजस्य के साथ कार्य करना होगा, ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। उन्होंने कृषि एवं

संबद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शासन की योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचाने पर जोर दिया। रबी वर्ष 2026-27 की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के लिए किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की

पुरानी रंजिश में नाबालिग पर जानलेवा हमला किया

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम लावर में पुरानी रंजिश को लेकर एक नाबालिग पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना रावण दहन के बाद बोथीडीह मिडिल स्कूल परिसर में हुई, जहां आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए चूड़ा और डंडे से नाबालिग के सिर, गले और हाथ पर हमला कर दिया। हमले में नाबालिग के सिर पर गंभीर चोट आई है। मामले में मस्तूरी पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चूड़ा और डंडा भी जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच ग्राम लावर-बोथीडीह के मिडिल स्कूल

परिसर में रावण दहन के बाद विवाद हुआ। बताया गया कि करीब दो माह पहले 17 वर्षीय भानू कैवर्त को एक अज्ञात लड़की के साथ पकड़े जाने की घटना को लेकर आरोपी अरुण खुटे उर्फ गुड्डु और उसके साथियों के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी बात को लेकर भानू कैवर्त ने अरुण खुटे से विवाद किया। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हाथ में पहने चूड़े और डंडे से उसके सिर, गले और हाथ पर हमला कर दिया। हमले में नाबालिग के सिर पर चोट आई, जबकि गले और हाथ में भी चोटें लगीं। ये पांच आरोपी गिरफ्तार प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक 773/2026 के तहत भारतीय न्याय

संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 191(1), 191(2), 109 एवं 324(4) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है: अरुण कुमार खुटे उर्फ गुड्डु सतनामी (21 वर्ष), पिता गणेश खुटे, निवासी ग्राम लावर, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर। संजीत कारके (27 वर्ष), पिता श्यामलाल कारके, निवासी ग्राम लावर, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर।संजू कारके (22 वर्ष), पिता श्यामलाल कारके, निवासी ग्राम लावर, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर। सिद्धार्थ उर्फ चिंदू कारके (26 वर्ष), पिता भुनेश्वर कारके, निवासी ग्राम लावर, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर।

स्वच्छ और कचरा मुक्त गांव बनाने पर जोर,राज्य सलाहकार ने किया स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण

■ घर-घर कचरा संग्रहण और कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश

बिलासपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने बिल्हा विकासखंड के ओडीएफ मॉडल ग्राम बिटकुली, पासीद, खम्हारडीह एवं मंगला (प) में दोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गांवों में स्वच्छता व्यवस्था, घर-घर कचरा संग्रहण और अपशिष्ट निपटान की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही स्वच्छ एवं कचरा मुक्त गांव बनाने के लिए ग्रामीणों की सक्रिय



भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती सिंह ने स्वच्छग्राहियों को दोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अंतर्गत कचरे को चार श्रेणियों सुखा, गोला, सेनेटरी एवं विशेष देखभाल वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे में

अलग-अलग रखने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए घरों से ही कचरे का पृथक्करण जरूरी है। ग्रामीणों को नियमित कचरा संग्रहण में सहयोग करने और स्वच्छता शुल्क का भुगतान

करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। श्रीमती सिंह ने घर-घर कचरा संग्रहण में संलान स्वच्छग्राही समूहों के सदस्यों से चर्चा कर उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने सरपंचों एवं सचिवों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले लोगों को पहले समझाइश दी जाए। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने गांवों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों के नियमित उपयोग और स्वच्छता बनाए रखने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर जिला समन्वयक, जनपद पंचायत की टीम, नोडल अधिकारी, सरपंच, पंच, सचिव, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बिहान समूह की महिलाएं, स्वच्छग्राही एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

प्राप्त निर्धारित प्रारूप के फ्लेक्स एवं होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए गए। सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क की सूची भी प्रत्येक केंद्र पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया, ताकि नागरिकों को शुल्क की सही जानकारी मिल सके। साथ ही केंद्रों में हितग्राहियों के बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की 900 से अधिक सेवाएं नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें 125 से अधिक सेवाएं सीधे पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इन सेवाओं का लाभ नागरिकों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए जिले में केंद्र प्रबंधकों का प्रशिक्षण एवं कार्यों की समीक्षा निरंतर की जा रही है।

रतनपुर पुलिस की अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई

7 लीटर महुआ शराब जब्त



(भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले में नशे के कारोबार में संलित लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी रतनपुर निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में अवैध शराब, गांजा एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर

निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में 21 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गांधीनगर रतनपुर में दबिश दी। इस दौरान आरोपी कमलेश निर्मलकर उर्फ गोलू (30 वर्ष), पिता रामशरण निर्मलकर, निवासी गांधीनगर रतनपुर, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर के कब्जे से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब और बिक्री की रकम 1,100 रुपये बरामद की गई।

नवाचार को प्रोत्साहन युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान



■ सीएमडी महाविद्यालय में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बिलासपुर। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा सीएमडी महाविद्यालय में 'सेवा फर्स्ट इनिवेशन चैलेंज 2026' एवं उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा उनके नए विचारों के उचित मंच प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक सुनील कुमार पाण्डेय ने प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत 10 विभिन्न सेक्टरों से नवीन एवं उपयोगी विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रत्येक सेक्टर से पांच विजेताओं का चयन किया जाएगा। इनमें एक स्थान महिला प्रतिभागियों तथा एक स्थान 21 वर्ष से कम आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए आरक्षित रहेगा। इस प्रकार कुल 50 विजेताओं का चयन किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता

के तहत कुल पांच करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसमें केवल विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि बाहर के इच्छुक प्रतिभागी और नवाचारकर्ता भी हिस्सा ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागीपोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। महाविद्यालय के चेयरमैन डॉ. संजय दुबे ने विद्यार्थियों को नए एवं विशिष्ट विचार प्रस्तुत करने और समाज तथा उद्योग की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। वहीं, प्रबंधक उत्तम कुमार दुबे ने स्वरोजगार संबंधी योजनाओं एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य संजय सिंह ने विद्यार्थियों एवं स्टाफ से प्रतियोगिता की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने तथा इच्छुक प्रतिभागियों को पंजीयन के लिए प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल सहित अन्य प्राध्यापकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस दौरान लगभग 60 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित थे।

